28-02-2024

पहला सफल लेजर कूल्ड पॉज़िट्रोनियम

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भौतिकविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने पहली बार पॉज़िट्रोनियम के लेजर कूलिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जो एक अल्पकालिक हाइड्रोजन जैसा परमाणु है। यह बाउंड-स्टेट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए एक आदर्श परीक्षण क्षेत्र उपलब्ध कराता है।
- एंटी-हाइड्रोजन के निर्माण के लिए शोधकर्ताओं ने ग्रेविटी, इंटरफेरोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी (एईजीआईएस) सहयोग से यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) में कई जटिल प्रयोग किए गए हैं। CERN की स्थापना 1954 में यूरोप में एक विश्व स्तरीय मौलिक भौतिकी अनुसंधान संगठन की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी।
- ये परिणाम उन्नत अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जिससे भौतिक प्रकृति की बेहतर समझ को बढ़ावा मिल सकता है, जिसमें प्रकाश और आवेशित पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से पदार्थ और एंटी-पदार्थ शामिल हैं।
- भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) में लाइट एंड मैटर ग्रुप के प्रोफेसर सादिक रंगवाला, एईजीआईएस सहयोग का हिस्सा हैं जिसमें 19 यूरोपीय समूहों के भौतिक विज्ञानी शामिल हैं और एक भारतीय समूह भी शामिल है।

पॉज़िट्रोनियम के बारे में

- पॉज़िट्रोनियम एक अल्पकालिक परमाणु है जो बाउंड-स्टेट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए एक आदर्श परीक्षण आधार प्रदान करता है।
- पॉज़िट्रोनियम एक मौलिक परमाणु है जो एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन (e-) और धनावेशित पॉज़िट्रॉन (e+) से मिलकर बना है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और पॉज़िट्रॉन लेप्टान हैं, और वे विद्युत चुम्बकीय और कमजोर बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं।
- एक सामान्य परमाणु बेरिऑन और लेप्टान के मिश्रण से बना होता है। चूँकि पॉज़िट्रोनियम केवल इलेक्ट्रॉनों और पॉज़िट्रॉन से बना है, और कोई सामान्य परमाणु पदार्थ नहीं है, इसलिए इसे

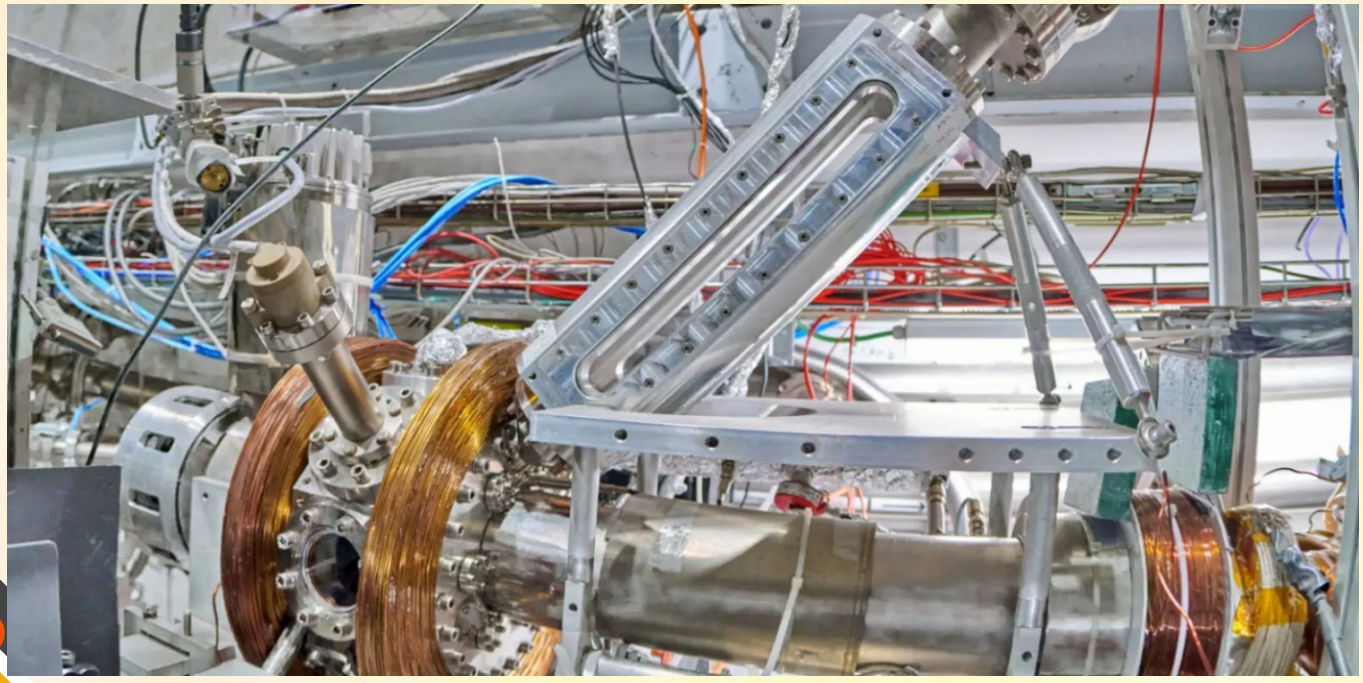

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

विशुद्ध रूप से लेप्टोनिक परमाणु होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

- इसका पता सबसे पहले 1951 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लगाया था।
- इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का दोगुना है और यह अपने अत्यंत अल्प जीवन के कारण, यह 142 नैनो-सेकंड के आधे जीवन के साथ नष्ट हो जाता है।

पॉज़िट्रोनियम के लेज़र कूलिंग का महत्व

- पॉज़िट्रोनियम को लेजर कूलिंग करने से परमाणुओं की गति धीमी हो जाती है, जिससे वैज्ञानिकों के लिए भौतिकी में मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन करना आसान हो जाता है।
- यह कण भौतिकी में उन्नत अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है | यह भौतिक प्रकृति की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिसमें प्रकाश और आवेशित पदार्थ के बीच बातचीत के माध्यम से पदार्थ और एंटी-मैटर शामिल हैं।
- यह एंटी-हाइड्रोजन के निर्माण और एंटीहाइड्रोजन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मापन के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत प्रयोग है।
- यह गामा-रे लेजर का उत्पादन करने की संभावनाएं खोल सकता है जो अंततः शोधकर्ताओं को परमाणु नाभिक के अंदर देखने की अनुमति देगा और इसमें भौतिकी से परे संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं।
- यह भविष्य के प्रयोगों के लिए एक आधार साबित हो सकता है | क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स (क्यूईडी) के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रोस्कोपिक तुलना करने के लिए, प्रकाश का अध्ययन और चार्ज किए गए पदार्थ के साथ इसकी बातचीत, और पॉज़िट्रोनियम की संभावित पतित गैस प्राप्त की जा सकती है।
- यह एंटीमैटर अनुसंधान के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न करेगी | यह सरल पदार्थ-एंटीमैटर प्रणाली के गुणों और गुरुत्वाकर्षण व्यवहार के उच्च-सटीक माप की अनुमति देगा, जो नई भौतिकी को प्रकट कर सकता है।
- यह पॉज़िट्रोनियम बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (बीईसी) के उत्पादन की भी अनुमति देता है, जिसमें सभी घटक समान क्वांटम अवस्था में होते हैं। बीईसी पदार्थ की एक अवस्था है जो तब होती है जब कणों को पूर्ण शून्य के करीब ठंडा किया जाता है और एक एकल क्वांटम वस्तु में एकत्रित किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत में प्रतिवर्ष 26 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर (Veer Savarkar) की पुण्यतिथि मनाई जाती है। गौरतलब है कि उनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था और वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 28 मई, 1883 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था।
- उनके द्वारा ही 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया था। सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन और लन्दन में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। वे वर्ष 1937 से 1943 के बीच हिन्दू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे।
- उन्होंने अपने जीवन में पुस्तकें भी लिखी जिसमें एक 'जोसफ मैजिनी – जीवन कथा व राजनीती' थी। उन्होंने एक 'द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस' नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया जो वर्ष 1857 की क्रान्ति पर रचित थी। इसके अलावा रत्नागिरी में कैद के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक 'हिंदुत्व – हू इज हिन्दू' है।
- ध्यातव्य रहे, सावरकर के सम्मान में अंडमान व निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के हवाईअड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा रखा गया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 26 फरवरी, 2024 को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (NICDC), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली स्थित नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

फाउंडेशन (एफआईटीटी- आईआईटीडी) ने पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करके राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम स्थानों का आंकलन करने के उद्देश्य से वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- यह सहयोग भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोनों संगठनों को अपने-अपने क्षेत्रों में एक-दूसरे की ताकत का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी।
- इस सहयोग से पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल के स्थानिक और विश्लेषणात्मक डेटा टूल का लाभ उठाकर पूरे देश में ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए अनुकूलतम स्थानों का आकलन करने में मदद मिलेगी। यह पहल वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के भारत के विजन के अनुरूप है, जो टिकाऊ भविष्य की शहरी योजना और विकास में डेटा-संचालित, निर्णय लेने के महत्व पर जोर देती है।
- एमओयू के अंतर्गत, एफआईटीटी-आईआईटीडी स्थान की इष्टतमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने के लिए अपनी तकनीकी कौशल और अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाएगा, जिसमें व्यापार में आसानी, रहने-सहने की लागत, लॉजिस्टिक लागत, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, विशेष उद्योगों की संभावना, कच्चे माल की उपलब्धता और स्थिरता की क्षमता शामिल है।
- इस सहयोग के परिणामस्वरूप तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट भविष्य के शहरी नियोजन निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शक फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगी, जो उद्योग और समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड शहरों के विकास को आसान बनाएगी।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (एनआईसीपी) भारत सरकार का एक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटीज़" के रूप में विकसित करना और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में परिवर्तित करना है।
- इसका उद्देश्य भारत में ऐसे औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो विश्व के सबसे अच्छे विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को शुरू किया गया है और इसके तहत वर्ष 2024-25 तक चार चरणों में कुल 30 परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा।
- एनआईसीपी की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अधीन है। इसकी शुरुआत 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में हुई थी।

ई-सत्यापन योजना-2021 का कार्यान्वयन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, आयकर विभाग ने ब्याज एवं लाभांश आय पर तृतीय पक्ष की जानकारी और करदाताओं द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों का पता लगाया है। कई मामलों में करदाताओं ने तो यहां तक कि अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

- विसंगति को दूर करने के लिए करदाताओं को अपना जवाब देने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुपालन पोर्टल में एक ऑन-स्क्रीन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑन-स्क्रीन करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके पोर्टल पर ही बेमेल का समाधान करने की सुविधा देगी। इसके लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यह करदाताओं तक पहुंचने और उन्हें संरचना-आधारित तरीके से संचार का जवाब देने का अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा उठाया गया एक सक्रिय कदम है।
- वर्तमान में अनुपालन पोर्टल पर वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी विसंगति प्रदर्शित की गई है। विभाग के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी विसंगति के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

ई-सत्यापन योजना-2021 क्या है?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 13 दिसंबर 2021 की एक अधिसूचना के माध्यम से ई-सत्यापन योजना, 2021 प्रकाशित की है। यह योजना फेसलेस सूचना संग्रह का आकलन और उसके सत्यापन को कवर करती है।
- यह योजना करदाता के पंजीकृत खाते पर अपलोड की गई जानकारी के बेमेल से निपटने के लिए लागू होगी।
- ई-सत्यापन योजना को आयकर अधिनियम 135ए के एक प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया है, जो आयकर प्राधिकरण और निर्धारिती के बीच इंटरफेस को समाप्त करके दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करने के उद्देश्य से फेसलेस सूचना एकत्र करने का प्रस्ताव करता है।
- यह सीबीडीटी विभाग के संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने का भी प्रयास करता है।
- योजना का दायरा आयकर अधिनियम की धारा 133, 133बी, 133सी, 135 के तहत जानकारी एकत्र करने के संबंध में होगा। यदि आयकर अधिनियम की धारा 134 के तहत तकनीकी रूप से व्यवहार्य सीमा तक कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण बिना पहचान के किया जाना है तो जानकारी भी एकत्र की जाएगी।

होमोसेप एटम

सुर्खियों में क्यों?

- "होमोसेप एटम" जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, भारत का पहला सेप्टिक टैंक/मैनहोल सफाई रोबोट है | इसका उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना है |
- यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एंड-टू-एंड समाधान पेश करता है और देश के विभिन्न कोनों में स्वच्छता अभियान को मजबूत कर रहा है।

- इसका विकास आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)-टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) में स्थापित एक स्टार्टअप द्वारा किया गया है |
- यह तकनीक पारंपरिक मैनुअल सफाई विधियों को रोबोटिक में बदल देती है। इसकी क्षमताओं में व्यापक ब्लेड सफाई, ठोस अपशिष्ट डीसिल्टिंग, सक्शन और भंडारण शामिल है, सभी एक डिवाइस में एकीकृत हैं।
- होमोसेप एटम रोबोट को पूरे भारत के 16 शहरों में तैनात किया गया है।

गर्भवती महिला में भ्रूण की आयु निर्धारित करने के लिए विशिष्ट मॉडल

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी नवाचार एवं अनुसन्धान परिषद – ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला में भ्रूण की आयु को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए एक भारत के लिए उपयुक्त विशिष्ट मॉडल विकसित किया है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

GARBH-INI (गर्भिणी) कार्यक्रम के बारे में

- नव विकसित गर्भकालीन आयु (GA) फॉर्मूला को गर्भिणी (GARBH-IN)-जीए 2 कहा गया है जो भारतीय जनसंख्या के लिए भ्रूण की आयु का सटीक अनुमान लगाता है, जिससे त्रुटि लगभग तीन गुना कम हो जाती है।
- गौरतलब है कि वर्तमान में, भ्रूण की आयु [गर्भकालीन आयु (Gestational Age- GA)] पश्चिमी देशों की जनसंख्या के लिए विकसित फार्मूले का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और इसके भारतीय जनसंख्या में भ्रूण की वृद्धि में भिन्नता के कारण गर्भावस्था के बाद के भाग में लागू होने पर गलत होने की संभावना होती है।
- GARBH-INI (गर्भिणी) कार्यक्रम को जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत पहल के रूप में की गई है जिसे भारतीय जनसंख्या डेटा का उपयोग करके विकसित और शुरू में मान्य किया गया है।
- गर्भिणी –जीए 2 जो नियमित रूप से मापे जाने वाले तीन भ्रूण अल्ट्रासाउंड मापदंडों का उपयोग करता है, को हरियाणा के गुरुग्राम सिविल अस्पताल में प्रलेखित जीएआरबीएच-आईएनआई समूह डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया था, और शुरुआत में इसे दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र समूह में मान्य (वैलिडेट) किया गया था।
- अल्ट्रासाउंड डेटिंग प्रारंभिक गर्भावस्था में जीए का निर्धारण करने के लिए देखभाल का मानक है। यद्यपि भारत में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में अपना पहला अल्ट्रासाउंड कराता है। बेहतर सटीकता के साथ इन महिलाओं में भारतीय जनसंख्या -विशिष्ट जीए फ़ॉर्मूले का अनुप्रयोग संभावित रूप से गर्भावस्था देखभाल में सुधार कर सकता है और जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- यह सटीक डेटिंग देश में गर्भावस्था के परिणामों के लिए महामारी विज्ञान के अनुमानों की सटीकता को भी बढ़ाएगी। एक बार संभावित अखिल भारतीय समूहों में मान्य (वैलिडेट) होने के बाद, इस गर्भिणी –जीए 2 को पूरे भारत के क्लीनिकों में लागू किया जा सकता है जिससे प्रसूति विशेषज्ञों (आब्स्टिट्रिशियन्स) और नवजात शिशु विशेषज्ञों (नियोनेटोलोजिस्ट्स) द्वारा दी जाने वाली देखभाल में सुधार होगा तथा परिणामस्वरूप भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।

पर्पल उत्सव

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 26 फरवरी, 2024 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में एक दिवसीय 'पर्पल उत्सव' का आयोजन किया रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा की गई|
- ध्यान रहे, 8 से 13 जनवरी, 2024 तक गोवा में 'इंटरनेशनल पर्पल उत्सव, 2024' का आयोजन किया गया था|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस उत्सव की नोडल एजेंसी पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान है।
- इस भव्य स्थल पर 10 हजार से अधिक

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

दिव्यांगजन भी अपने अनुरक्षकों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

- 'पर्पल उत्सव' में सुगम्यता, समावेशन और दिव्यांगता अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठनों के पूरी तरह से समावेशी और इंटरैक्टिव स्टॉल रहेंगे। 'पर्पल उत्सव' की प्रमुख गतिविधियाँ अमृत उद्यान यात्रा, अपनी दिव्यांगताओं को जानें, पर्पल कैफे, पर्पल कैलीडोस्कोप, पर्पल लाइव एक्सपीरियंस ज़ोन, पर्पल स्पोर्ट्स आदि होंगी।
  यह उत्सव सभी के लिए अधिक समावेशी और सुलभ समाज के निर्माण हेतु अपने विचारों और अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करने का एक मंच है।
- इस उत्सव का उद्देश्य विभिन्न विकलांगताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और लोगों पर इसका प्रभाव और दिव्यांगता में विचरित गलत धारणाओं, अभिशाप और रूढ़िवादिता को चुनौती देना और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेशन को प्रोत्साहन देना है।

किशोरियों में पोषण सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन

सुर्खियों में क्यों?

- 26 फरवरी, 2024 को विज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी और केंद्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में किशोरियों में पोषण सुधार के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के द्वारा किशोरियों में पोषण सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया गया | विदित है कि दोनों मंत्रालय मिलकर पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने, संयुक्त योग प्रोटोकॉल के माध्यम से कल्याण को बढ़ावा देने और स्थानीय रूप से उगाए गए पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत के माध्यम से आहार विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
- आयोजन के दौरान, 5 उत्कर्ष जिलों में किशोरियों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए| ध्यान रहे, मिशन उत्कर्ष की शुरुआत जनवरी 2022 में की गई थी। इसके तहत 15 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग जिलों में चुनिंदा प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को राज्य और राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- यह पहल महिलाओं और बच्चों के बीच समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और तकनीकों को शामिल करते हुए आयुर्वेद जैसी पारंपरिक स्वास्थ्य

देखभाल प्रणालियों की ताकत का उपयोग करना चाहता है।

- गौरतलब है कि पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं में निहित पोषण समाधान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (पोषण 2.0) का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत कई प्रयास और रणनीतियाँ प्रमुख मंत्रालयों और विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से निपटने का प्रयास करती हैं।
- स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन से जुड़ी कमियों को कम करने के लिए, पोषण 2.0 का सामान्य केंद्र आयुष के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य न केवल कुपोषण की कमी को दूर करना है, बल्कि मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों और एमएएम/एसएएम बच्चों के उपचार पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
- पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे राष्ट्रीय सामुदायिक आयोजनों के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं।

पोषण अभियान के बारे में

- पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) कुपोषण को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिये भारत सरकार (GoI) की एक प्रमुख पहल है जिसे 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) तथा जन्म के समय वजन में कमी को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है।
- इसका लक्ष्य एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम तैयार करना है जो पोषण सेवाओं हेतु सामग्री, उनका वितरण, आउटरीच और समग्र परिणामों में वृद्धि करेगा।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य उन प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो बीमारियों और कुपोषण की समस्या का समाधान कर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, कल्याण तथा प्रतिरक्षा में सुधार करती हैं।
- यह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लक्षित करता है।

सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 क्या है?

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार (GoI) ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) और पोषण (प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना) अभियान को सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया।
- इसके तहत ICDS एवं पोषण अभियान के साथ किशोरियों के लिये योजना (SAG) एवं राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को भी पुनर्गठित किया गया है|
- पोषण 2.0 केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया जा रहा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।
- यह 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों (14-18 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच कुपोषण की चुनौतीपूर्ण स्थिति का समाधान करेगा।
- इसका उद्देश्य आँगनबाडी सेवाओं के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिये व्यापक रणनीति तैयार करना है।
- इसके तहत आकांक्षी ज़िलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों (एनईआर) में 06 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PWLM) और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिये पूरक पोषण कार्यक्रम (SNP) के माध्यम से पोषण सहायता दी जाएगी|

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)